

ग्रामीण क्रेडिट स्कोर

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

[केंद्रीय बजट 2025-26](#) में [सवयं सहायता समूहों \(SHG\)](#) और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये [ग्रामीण क्रेडिट स्कोर \(GCS\)](#) फ्रेमवर्क परस्तुत किया गया।

ग्रामीण क्रेडिट स्कोर:

- **परिचय:** इसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा **ग्रामीण परविश के व्यक्तियों की ऋण पात्रता का आकलन करने** तथा ऋण प्राप्ति को सुवधाजनक बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
 - इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में **उधारकर्ताओं (ऋण प्राप्तकर्ता) का अधिक सटीक मूल्यांकन** प्रदान कर ऋण चुकौती अनुशासन में सुधार लाना तथा **धोखाधड़ी को कम करना** है।
- **प्रभाव:** यह **माइक्रोफाइनेंस को मजबूत करेगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा** तथा कृषि, ग्रामीण विकास और MSME जैसे क्षेत्रों को सहायता प्रदान करेगा।
 - GCS मौजूदा **माइक्रोफाइनेंस मॉडलों का पूरक** होगा तथा ऋणों के मूल्यांकन के लिये CIBIL और CRIF **हाईमार्क जैसे क्रेडिट स्कोर** के साथ मलिकर कार्य करेगा।
 - इस **स्कोर को स्वामित्व योजना के साथ एकीकृत** किया जाएगा।

अन्य पहल:

- **भारतीय डाक का रूपांतरण:** [केंद्रीय बजट 2025](#) में भारतीय डाक को **1.5 लाख डाकघरों और 2.4 लाख डाक सेवकों** के विशाल ग्रामीण नेटवर्क का उपयोग करते हुए एक प्रमुख **सार्वजनिक रसद संगठन** में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया गया है।
- **राष्ट्रीय सहकारी विकास नगिम (NCDC) के लिये सहायता:** **सहकारी क्षेत्र को ऋण देने को बढ़ावा देने के लिये सहकारी चीनी मिलों को मजबूत** करने के लिये 500 करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित किया गया।

और पढ़ें: [केंद्रीय बजट 2025-26, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, स्वामित्व योजना](#)